गन्ना किसानों को राहत

गन्ना किसानों को मिलेगी 5.5 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी

ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली

सरकार ने चीनी मिलों की ओर से सीधे किसानों को 5.5 रुपये प्रति क्विंटल की उत्पादन सब्सिडी देने को मंजूरी दी है। इससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और चुनावी गहमागमी से गुजर रहे कर्नाटक के गन्ना किसानों को राहत मिलेगी। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी के दाम में गिरावट से गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर करीब 20,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को गन्ना किसानों के लिए 55 रुपये प्रति टन (5.5 रुपये प्रति क्विंटल) प्रॉडक्शन लिंक्ड सब्सिडी देने को मंजूरी दी। सरकार ने यह फैसला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 12 मई को मतदान से पहले किया है। कर्नाटक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है।

उद्योग संगठन इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि चीनी उद्योग चीनी मिल गेट भाव में गिरावट के कारण भारी नुकसान का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी राशि 1,500 से 1,600 करोड़ रुपये हो सकती है। यह मिलों द्वारा मार्केटिंग ईयर 2017-18 (अक्तूबर-सितंबर) में गन्ने की पेराई पर आधारित होगी। इस्मा के अनुसार, देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ने से चीनी उत्पादन 15 अप्रैल तक बढ़कर 2.99 करोड़ टन तक पहुंच गया। इसके कारण किसानों के गन्ने का बकाया 20,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया। देश में चीनी की सालाना मांग ढाई करोड़ टन तक आंकी गई है। इससे पहले 2016-17 में चीनी का उत्पादन 2.03 करोड़ टन रहा था। घरेलू स्तर पर चीनी के बढ़ते उत्पादन और गिरते दाम को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीनी आयात पर शुल्क को पहले ही बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया था जबकि निर्यात पर शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सरकार ने मिलों से 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने को भी कहा है।

इस्मा के मुताबिक, सब्सिडी की रकम 1,500 से 1,600 करोड़ रुपये हो सकती है

The Economic Times - (Hindi)
03-05-18.